THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b). Streamlining of the Department of Customs and Central Excise is a continuing process. Various steps have been taken in this regard in the recent past and more are underway. A comprehensive Central Excise Bill to replace the existing Central Excises and Salt Act, 1944, is in the process of being drafted. The Estimates Committee of the Parliament is also expected to look into some important aspects of the functioning of the Department and make recommendations which could be taken into consideration while drafting the Bill.

बैंक नोट प्रेस, देवास के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं

949. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक नोट प्रेस, देवास के उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये कदाचारों और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतें संघों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की ओर से मिली हैं तथा उनके नाम क्या है तथा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बैंक नोट प्रेस, देवास के उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिनके बारे में शिकायतें मिली हैं, जांच की है और यदि हां, तो जांच किन एजेन्सियों से कराई गई है तथा जांच के क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1975 से, सरकार को बैंक नोट प्रेस कर्मचारी संघ, देवास और सर्व श्री अजय सिंह, राजकुमार कपूर और पी० सी० जोशी नामक बैंक नोट प्रेस के कर्मचारियों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों की विभागीय जांच करायी गई और इनको निराधार पाया गया। इन तीन कर्मचारियों के मामलों को कर्मचारी संघ द्वारा औद्योगिक विवाद के रूप में लिया गया और इनको समझौते के लिए ले लिया गया और इस समय ये मामले श्रमिक तंत्र अथवा औद्योगिक अधिकरण के पास न्याय निर्णय के लिए पड़े है। निर्णय की प्रतीक्षा अभी की जा रही है।

अप्रैल, 1977 से, बैंक नोट प्रेस के अधिकारियों के विरुद्ध खरीदारी आदि के मामलों में कदाचारों और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में की गई कुछ गुमनाम शिकायतों की विभागीय जांच कराई गई परन्तु उनमें कुछ सार नहीं पाया गया। खरीद दारी आदि में अनियमितताओं आदि से सम्बन्धित कुछ अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है। इस अवस्था में इन शिकायतों के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ कहना उचित नहीं होगा।

James Raj Committee Report on Public Sector Banks

950. SHRI P. K. KODIYAN :
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the James Raj Committee on the Public Sector Banks has submitted an Interim Report to the Government;

(b) if so, what are the recommendations thereof;

(c) Government's decision thereon; and

(d) what benefits will be borrowers get in the light of the recommendations of the said Committee ?